

सहकार सुगंध

सहकारिता की सुगंध फैलाने वाला राष्ट्रीय पत्र



आत्मनिर्भर भारत में सहकारी संस्थाओं की बदलती भूमिका और नए मॉडल।

सहकार भारती क्या है?.....	3
स्थापना और संस्थापकों का योगदान.....	3
सहकार भारती की स्थापना कब और क्यों हुई?.....	3
संस्थापकों का परिचय.....	3
सहकार भारती का वैचारिक आधार.....	4
सहकार से समृद्धि का सिद्धांत.....	4
सहकारिता और भारतीय संस्कृति.....	4
सहकार भारती का संगठनात्मक ढांचा.....	4
राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर तक का नेटवर्क.....	4
टिभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका.....	4
सहकार भारती की प्रमुख गतिविधियाँ.....	5
प्रशिक्षण और नेतृत्व निर्माण.....	5
सहकारिता को आधुनिक तकनीक से जोड़ना.....	5
युवाओं और महिलाओं को सहकारिता से जोड़ना.....	5
सहकार भारती की राष्ट्रीय भूमिका.....	5
आत्मनिर्भर भारत में योगदान.....	5
सरकार और सहकारी क्षेत्र के बीच सेतु.....	5
सहकार भारती का भविष्य इष्टिकोण.....	6
सहकारिता का आधुनिकीकरण.....	6
युवाओं को सहकारिता के केंद्र में लाना.....	6
सहकार सुगंध : सहकारिता की सुगंध फैलाने वाला राष्ट्रीय पत्र.....	6
सहकार सुगंध क्या है?.....	6
सहकार भारती का प्रकाशन – सहकार सुगंध की पृष्ठभूमि.....	6
सहकारिता के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता.....	6
जन-जन तक सहकारिता की सुगंध.....	6
सहकार सुगंध का विज्ञन और उद्देश्य.....	7
सहकारिता को आधुनिक और प्रभावी बनाना.....	7
सहकारी कार्यकर्ताओं को दिशा देना.....	7
सहकारिता को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाना.....	7
सहकार सुगंध की प्रमुख विशेषताएँ.....	7
सरल, प्रभावी और प्रेरक सामग्री.....	7
क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कवरेज.....	7
विशेषज्ञों के विश्लेषण और विचार.....	7
सहकार सुगंध में प्रकाशित होने वाले प्रमुख सेक्शन.....	8
सहकार समाचार झरोखा.....	8
प्रेरक कहानियाँ और सफलता के मॉडल.....	8
विशेषज्ञ लेख और विश्लेषण.....	8
युवा सहकार मंच.....	8
महिला शक्ति विशेष.....	8
तकनीक और नवाचार.....	8
राज्य-विशेष रिपोर्ट.....	8
सहकार सुगंध की संपादकीय इष्टि.....	8
तथ्यात्मक और विश्वसनीय सामग्री.....	8
सहकारिता के मूल सिद्धांतों पर आधारित.....	9
पाठक-कैंट्रिट लेखन शैली.....	9
पाठकों का वर्ग (Readership).....	9
सहकारी समितियों के सदस्यों.....	9

किसान और ग्रामीण उद्यमी.....	9
शिक्षाविद, शोधकर्ता और नीति निर्माता.....	9
युवा और महिला उद्यमी.....	9
सहकार सुगंध का भविष्य दृष्टिकोण.....	9
डिजिटल संस्करण की ओर अग्रसर.....	9
नए युग की सामग्री.....	10
राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता का एकीकृत मंच.....	10
सहकारिता — मतलब क्या और यह कैसे काम करती है.....	10
2025-2026: सहकारिता में ताज़ा तथ्य और बड़ी खबरें.....	10
नई National Cooperative Policy 2025 (NCP 2025) — सहकारिता को नया आयाम.....	10
सहकारिता + नवाचार + विस्तार — अब दिशा बदल रही है.....	11
सहयोगी संस्थाओं की संख्या और फैलाव.....	11
चुनौतियाँ — और सहकारिता में सुधार की ज़रूरत.....	11
नेताओं का दृष्टिकोण — सहकारिता अब भविष्य की शक्ति.....	12
Amit Shah — “सहकारिता = आत्मनिर्भरता + नवाचार”.....	12
राज्य-नेता और स्थानीय नेतृत्व — ग्रामीण विकास व समान अवसर.....	12
सहकारिता का सामाजिक व आर्थिक महत्व — क्यों अब ज़रूरी है.....	13
आगे की दिशा — सहकारिता का भविष्य.....	13
सहकारिता समाज, किसान और सरकार के लिए कैसे मददगार है?.....	13
सहकारिता की मूल भावना और सामाजिक प्रभाव.....	14
सामाजिक एकता और सामूहिक निर्णय.....	14
रोजगार और कौशल विकास.....	14
आर्थिक समावेशन.....	14
किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सहकारिता की भूमिका.....	14
किसान की लागत घटाना और उपज बढ़ाना.....	15
फसल का उचित मूल्य और बाजार तक पहुंच.....	15
कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा.....	15
सरकार के लिए सहकारिता की उपयोगिता.....	15
विकास योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन.....	15
स्थानीय स्तर पर शासन को मजबूत बनाना.....	16
अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विश्वसनीयता.....	16
समाज, किसान और सरकार — तीनों के लिए लाभदायक मॉडल.....	16
समाज के लिए.....	16
किसानों के लिए.....	17
सरकार के लिए.....	17

आत्मनिर्भर भारत में सहकारी संस्थाओं की बदलती भूमिका और नए मॉडल।

सहकार भारती क्या है?



सहकार भारती भारत की एक प्रमुख स्वैच्छिक, गैर-राजनीतिक और राष्ट्रीय संगठन है, जो देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने, विस्तार देने और उसे आधुनिक जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के लिए कार्य करती है।

इसका मुख्य उद्देश्य है—सहकारिता को आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास का मजबूत आधार बनाना। यह संगठन सहकारी संस्थाओं, समितियों, किसानों, श्रमिकों, युवाओं और महिलाओं को सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता है।

सहकार भारती पूरे भारत में सहकारी सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण, नेतृत्व निर्माण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से एक व्यापक सहकार संस्कृति विकसित कर रहा है।



स्थापना और संस्थापकों का योगदान

सहकार भारती की स्थापना कब और क्यों हुई?

सहकार भारती की स्थापना वर्ष 1978 में इस उद्देश्य से हुई कि भारत में सहकारिता को केवल आर्थिक गतिविधि के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विकास के मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए।

इसकी नींव इस विचार पर रखी गई कि भारत के लाखों ग्रामीण और शहरी परिवार, संगठित सहयोग के माध्यम से, अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

संस्थापकों का परिचय

सहकार भारती की स्थापना के प्रेरक और प्रमुख नेतृत्वकर्ता लक्ष्मणराव इंगे, भाऊराव देवरस, और अन्य सहकार-समर्थक कार्यकर्ता थे।

इन नेताओं का मानना था कि भारत के आर्थिक विकास में सहकारिता सबसे लोकतांत्रिक, न्यायसंगत और सामुदायिक मॉडल है।

इन संस्थापकों ने संगठन को केवल संस्थागत रूप नहीं दिया, बल्कि सहकारिता को जन-जन तक पहुँचाने का आंदोलन बनाया।

सहकार भारती का वैचारिक आधार

सहकार से समृद्धि का सिद्धांत

संगठन का मूल विश्वास है—"सबका साथ, सबकी भागीदारी और सबकी समृद्धि"। सहकारिता का अर्थ केवल आर्थिक गतिविधियाँ नहीं, बल्कि सामूहिक सोच, साझा विकास और सामाजिक upliftment है।

सहकारिता और भारतीय संस्कृति

भारतीय परंपरा में सहयोग, साझेदारी और सामुदायिक जीवन का गहरा आधार है। सहकार भारती इसी सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक आर्थिक प्रणाली से जोड़कर एक भारतीय मॉडल की सहकारिता प्रस्तुत करता है।

सहकार भारती का संगठनात्मक ढांचा

राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर तक का नेटवर्क

सहकार भारती का नेटवर्क पूरे देश में फैला है—

- राष्ट्रीय कार्यालय
- राज्य एवं क्षेत्रीय इकाइयाँ
- ज़िला और स्थानीय शाखाएँ

यह संरचना संगठन को जमीनी स्तर तक पहुँचने और हजारों सहकारी संस्थाओं तक मार्गदर्शन पहुँचाने में सक्षम बनाती है।

विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका

सहकार भारती बैंकिंग, कृषि, उद्योग, जन-कल्याण, कौशल विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, SHG समूह, FPO, डेयरी, पशुपालन, युवा मंच और महिला सहकार जैसे कई क्षेत्रों में काम करता है।



सहकार भारती की प्रमुख गतिविधियाँ

प्रशिक्षण और नेतृत्व निर्माण

संगठन नियमित रूप से प्रशिक्षण शिविर, कार्यशालाएँ और awareness programs आयोजित करता है, जिससे सहकारी संस्थाओं को बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और नवाचार अपनाने में मदद मिलती है।

सहकारिता को आधुनिक तकनीक से जोड़ना

सहकार भारती नई तकनीक, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप, e-governance और डेटा-आधारित प्रबंधन को सहकारी संस्थाओं में बढ़ावा देता है।

युवाओं और महिलाओं को सहकारिता से जोड़ना

युवा सहकार मंच, महिला मंच (महिला सहकार) और उद्यमिता कार्यक्रम संगठन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो नई पीढ़ी को सहकारिता के माध्यम से आर्थिक विकास में भागीदारी के अवसर देते हैं।

सहकार भारती की राष्ट्रीय भूमिका

आत्मनिर्भर भारत में योगदान

सहकार भारती ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उत्पादन, स्थानीय उद्योगों, किसान समूहों और सहकारी समितियों को मजबूत बनाकर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सशक्त बना रहा है। संगठन को विश्वास है कि सहकारिता भारत के विकास मॉडल का मूल आधार बन सकती है।

सरकार और सहकारी क्षेत्र के बीच सेतु

सहकार भारती सरकार की सहकारिता नीतियों, मंत्रालयों और संस्थाओं के साथ मिलकर नीति सुझाव, प्रशिक्षण मॉडल, नवाचार और सार्वजनिक सहभागिता को आगे बढ़ाता है।

Sample Advertisement

सिंकंदराबाद सहकारी क्रय-विक्रय समिति, सिंकंदराबाद (बुलंदशहर)

सहकार भारती उत्तर प्रदेश के 5वें प्रदेश अधिवेशन में आए
सभी सहकारी बंधुओं एवं बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

जय भगवान त्रिवेदी
आद्यक्ष

मनोज कुमार
सचिव

सहकार भारती का भविष्य दृष्टिकोण

सहकारिता का आधुनिकीकरण

आने वाले वर्षों में सहकार भारती डेटा-ड्रिवन मॉडल, डिजिटल FPO, तकनीकी पारदर्शिता और आधुनिक प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

युवाओं को सहकारिता के केंद्र में लाना

संगठन का लक्ष्य है कि भारत का युवा—स्टार्टअप संस्कृति, कृषि—आधारित नवाचार और सामाजिक उद्यमिता—सहकारिता के माध्यम से नए अवसर प्राप्त करें।

सहकार सुगंध : सहकारिता की सुगंध फैलाने वाला राष्ट्रीय पत्र

सहकार सुगंध क्या है?

सहकार सुगंध सहकार भारती द्वारा प्रकाशित एक प्रमुख राष्ट्रीय सहकार पत्रिका है, जिसका उद्देश्य सहकारिता के विचार, मूल्य, गतिविधियाँ और सफल मॉडलों को समाज तक पहुँचाना है। इस पत्रिका का मिशन है—भारत के सहकारी आंदोलन को सही जानकारी, प्रेरणा और दिशा प्रदान करना।

Sample Advertisement

कानपुर औद्योगिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेट लिमिटेड

सुरेश पुरी
अध्यक्ष

हमारा लक्ष्य सहकारिता के माध्यम से उद्योगों का विकास है।

यह पत्रिका सहकारी संस्थाओं के क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कार्यकर्ताओं, सदस्यों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और उद्यमियों को एक साझा मंच प्रदान करती है, जहाँ वे अनुभव, ज्ञान और नवाचारों को साझा कर सकते हैं।

सहकार भारती का प्रकाशन – सहकार सुगंध की पृष्ठभूमि

सहकारिता के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता

भारत में सहकारिता का इतिहास पुराना है, लेकिन इसकी वास्तविक शक्ति समाज तक पहुँचाने के लिए एक प्रभावी माध्यम की आवश्यकता थी।

इसी उद्देश्य से सहकार भारती ने सहकार सुगंध का प्रकाशन शुरू किया—ताकि सहकारिता केवल पुस्तकों तक सीमित न रहे, बल्कि लोगों की सोच, काम और व्यवहार में शामिल हो।

जन-जन तक सहकारिता की सुगंध

संगठन ने इस पत्रिका को ऐसा स्वरूप दिया है जो आम जनमानस के लिए सरल, सहकारी क्षेत्र के लिए उपयोगी, और नीति-निर्माण के लिए सूचनात्मक हो।

सहकार सुगंध अपने नाम की तरह—सहयोग, विकास और सकारात्मक बदलाव की सुगंध देशभर में फैलाने का कार्य करता है।

सहकार सुगंध का विज्ञन और उद्देश्य

सहकारिता को आधुनिक और प्रभावी बनाना

पत्रिका का उद्देश्य है कि भारत में सहकारी संस्थाएँ केवल पारंपरिक संरचनाओं में न चलें, बल्कि तकनीकी, डिजिटल और नवाचार आधारित मॉडल अपनाएँ।

सहकारी कार्यकर्ताओं को दिशा देना

सहकार सुगंध उन सभी लोगों के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करता है, जो सहकारिता के सिद्धांतों को अपने क्षेत्र में लागू करना चाहते हैं—चाहे वह कृषि, बैंकिंग, डेयरी, लघु उद्योग, हस्तकला, ग्रामीण विकास या कौशल विकास हो।

सहकारिता को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाना

पत्रिका का एक प्रमुख लक्ष्य है कि सहकारिता को भारत की आर्थिक और सामाजिक नीतियों में एक महत्वपूर्ण स्थान मिले।

सहकार सुगंध की प्रमुख विशेषताएँ

सरल, प्रभावी और प्रेरक सामग्री

पत्रिका की भाषा सरल, स्पष्ट और आम जनता के लिए समझने योग्य है। इसका उद्देश्य जान देना ही नहीं, बल्कि प्रेरित करना भी है।

क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कवरेज

इसमें राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य और ज़िला स्तर तक सहकारी गतिविधियों का विस्तृत विवरण शामिल होता है—जिससे पाठक पूरे भारत में चल रही पहलें जान पाते हैं।

विशेषज्ञों के विश्लेषण और विचार

पत्रिका में सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं और अनुभवी कार्यकर्ताओं के लेख शामिल होते हैं, जो पाठकों को वास्तविक और उपयोगी मार्गदर्शन देते हैं।



सहकार सुगंध में प्रकाशित होने वाले प्रमुख सेक्शन

सहकार समाचार झरोखा

देशभर की सहकारी गतिविधियों का ताज़ा अपडेट।

प्रेरक कहानियाँ और सफलता के मॉडल

FPO, SHG, डेयरी, किसान समूह, महिला सहकार समितियों की प्रेरणादायक कहानियाँ।

विशेषज्ञ लेख और विश्लेषण

सहकारिता कानून, नीति परिवर्तन, आर्थिक सुधारों और प्रबंधन कौशल पर आधारित लेख।

युवा सहकार मंच

युवाओं के लिए अवसर, प्रशिक्षण, स्टार्टअप आधारित सहकारी मॉडल और नेतृत्व लेख।

महिला शक्ति विशेष

महिला सहकार समितियों, SHG समूहों और उद्यमशील महिलाओं की उपलब्धियाँ और मार्गदर्शन।

तकनीक और नवाचार

सहकारिता में डिजिटल टूल, नई तकनीक, आधुनिक प्रबंधन और Best Practices।

राज्य-विशेष रिपोर्ट

भारत के विभिन्न राज्यों की सहकारी गतिविधियों, समितियों और उपलब्धियों का विस्तृत विश्लेषण।

सहकार सुगंध की संपादकीय वृष्टि

तथ्यात्मक और विश्वसनीय सामग्री

पत्रिका का संपादकीय बोर्ड सुनिश्चित करता है कि सभी लेख और रिपोर्ट वास्तविक डेटा, प्रामाणिक स्रोतों और जमीनी अनुभवों पर आधारित हैं।

सहकारिता के मूल सिद्धांतों पर आधारित

सामग्री हमेशा पारदर्शिता, न्याय, साझेदारी, सहयोग और सामुदायिक विकास जैसे मूल सिद्धांतों पर आधारित होती है।

पाठक-केंद्रित लेखन शैली

पत्रिका का लेआउट, भाषा और सामग्री इस तरह तैयार की जाती है कि सभी स्तरों के पाठक आसानी से समझ सकें।

पाठकों का वर्ग (Readership)

सहकारी समितियों के सदस्यों

FPO, PACS, डेयरी, बैंकिंग और SHG समूहों में कार्यरत लाखों सदस्य नियमित पाठक हैं।

किसान और ग्रामीण उद्यमी

कृषि आधारित सहकार मॉडल समझने के लिए यह पत्रिका उपयोगी है।

शिक्षाविद, शोधकर्ता और नीति निर्माता

सहकारिता पर कार्य करने वाले छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण संदर्भ पत्रिका है।

युवा और महिला उद्यमी

Yuva Sahakar & Mahila Sahakar के माध्यम से युवा और महिलाएँ सहकारी गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित होती हैं।

सहकार सुगंध का भविष्य वृष्टिकोण

डिजिटल संस्करण की ओर अग्रसर

पत्रिका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होकर अधिक पाठकों तक पहुँचने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

नए युग की सामग्री

अगले संस्करणों में स्टार्टअप मॉडल, ग्रामीण नवाचार, डिजिटल कृषि, टेक-आधारित सहकार और स्टेनोबल डेवलपमेंट पर अधिक फोकस किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता का एकीकृत मंच

लक्ष्य है कि सहकार सुगंध केवल पत्रिका न होकर—सहकारिता का राष्ट्रीय ज्ञान मंच बनकर उभरे।

सहकारिता — मतलब क्या और यह कैसे काम करती है

“सहकारिता” का मूल विचार है — साझा स्वामित्व और साझा प्रबंधन। यानी, एक समूह (किसान, श्रमिक, उपभोक्ता, कारीगर आदि) मिलकर — पूँजी, श्रम, संसाधन साझा करते हैं, मिल-जुलकर संस्था बनाते हैं, और फायदे व जोखिम सब सदस्य (members) में बाँटते हैं।

सहकार संस्था (co-operative society) में —

- सदस्य उसकी मालिक होती हैं,
- प्रबंधन लोकतांत्रिक होता है (हर सदस्य को एक वोट अधिकार),
- उद्देश्य सिर्फ मुनाफा नहीं रहता — बल्कि सामाजिक, आर्थिक समावेशन, सामूहिक हित व विकास होता है।

भारत में सहकारिता का इतिहास सदियों पुराना है — ग्रामीण दक्षिणा-पद्धतियों, मिल-भांट और सामूहिक कृषि/उत्पादन रिवाजों से। आधुनिक काल में सहकारिता ने कृषि क्रेडिट, किसान सहकार समितियाँ (PACS/FPO), डेयरी, ग्रामीण क्रेडिट बैंक, उपभोक्ता सहकार, कृषि विपणन, मछली पालन आदि क्षेत्रों में बड़ी भूमिका निभाई है।

2025-2026: सहकारिता में ताज़ा तथ्य और बड़ी खबरें



नई National Cooperative Policy 2025 (NCP 2025) — सहकारिता को नया आयाम

- 24 जुलाई 2025 को, भारत सरकार ने National Cooperative Policy 2025 को घोषित किया। इसका लक्ष्य है कि देश के हर गाँव/पंचायत में कम-से-कम एक सहकारी संस्था हो।
- इस नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को पेशेवर, पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
- नीति के तहत अगले कुछ वर्षों में 2 लाख नए बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ (PACS, डेयरी, मत्स्य, किसान उत्पादक संगठन आदि) स्थापित करने की योजना है।

सहकारिता + नवाचार + विस्तार — अब दिशा बदल रही है

- अब सहकारिता सिर्फ कृषि-किसानों या क्रेडिट-बैंक तक सीमित नहीं रही। सरकार और नीति निर्माताओं इसे देख रहे हैं — डिजिटल सेवा, हेल्थकेयर, शिक्षा, ऊर्जा, ऑर्गेनिक खेती, वित्तीय समावेशन जैसे नए क्षेत्रों में।

- 2025 को वैश्विक स्तर पर International Year of Cooperatives 2025 (IYC 2025) घोषित किया गया है। इससे सहकारिता आंदोलन को और समर्थन मिला है — सहकारिता को “स्टेनेबल विकास” और “सामाजिक समावेशन” का मॉडल माना जा रहा है।

सहयोगी संस्थाओं की संख्या और फैलाव

- भारत में अनुमानित लगभग **8.5** लाख से ज्यादा सहकारी समितियाँ हैं, जो करोड़ों लोगों को (किसानों, ग्रामीणों, श्रमिकों) रोजगार, वित्तीय सुविधा, सामाजिक सुरक्षा और सामूहिक विकास प्रदान करती हैं।
- सहकारिता क्षेत्र में सुधार के लिए 2023 में पारित विधिक सुधार (governance reforms) आए हैं, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा मिला है।

चुनौतियाँ — और सहकारिता में सुधार की ज़रूरत

हालाँकि सहकारिता में बहुत संभावनाएँ हैं, फिर भी कुछ चुनौतियाँ हैं:

- कई सहकारी संस्थाओं में प्रबंधन की कमजोरियाँ, पारदर्शिता की कमी, सीमित तकनीकी उपयोग, और **NPAs** / वित्तीय अस्थिरता देखने को मिलती हैं।
- डिजिटल उपकरणों और आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने में देरी — विशेषकर ग्रामीण व कम संसाधन वाले क्षेत्रों में — सहकारिता की गति को धीमा कर देती है।
- सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और स्थानीय नेतृत्व की कमी — कभी-कभी सहकार समितियाँ सिर्फ कागज़ों में सीमित रह जाती हैं, वास्तविक सामूहिक शक्ति नहीं बन पातीं।

नेताओं का दृष्टिकोण — सहकारिता अब भविष्य की शक्ति

Amit Shah — “सहकारिता = आत्मनिर्भरता + नवाचार”

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा है कि सहकारिता अब पारंपरिक सीमाओं से आगे निकल चुकी है। यह केवल कृषि या ऋण तक सीमित नहीं — बल्कि डिजिटल सेवाओं, हेल्थ, शिक्षा, ऊर्जा, ऑर्गनिक खेती और वित्तीय समावेशन तक फैल चुकी है।

उनके अनुसार, सहकारिता मॉडल भारत की “स्वावलंबी एवं समावेशी अर्थव्यवस्था” का आधार बन सकता है, जहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान, युवा और वंचित वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त हों।

राज्य-नेता और स्थानीय नेतृत्व — ग्रामीण विकास व समान अवसर

कई राज्यों में, स्थानीय नेतृत्व और सरकारें इस बदलाव को देख रही हैं। उदाहरण के लिए, उत्तराखण्ड में सहकारिता को ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण का मुख्य माध्यम बताया जा रहा है।

भविष्य की योजनाओं में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से — किसान, महिला, युवा, आदिवासी जैसे पिछड़े वर्गों को संगठित करना और उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाना शामिल है।

सहकारिता का सामाजिक व आर्थिक महत्व — क्यों अब ज़रूरी है

- सहकारिता सस्ते क्रेडिट, सामूहिक संसाधन, और साझा निर्णय-प्रक्रिया के जरिए गरीब, किसान, श्रमिक, ग्रामीण, वंचित समूहों को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाती है।
- सहकारी संस्थाएँ गाँव-पंचायत स्तर तक पहुँचकर — स्थानीय उत्पादन, स्थानीय विपणन, ग्रामीण रोजगार, लघु उद्योग, महिला-स्वरोजगार, किसान समूह आदि के द्वारा विकास और समावेशन सुनिश्चित कर सकती हैं।
- आधुनिक भारत में — जब बेरोजगारी, असंगठित कामगार, ग्रामीण विस्थापन, कृषि संकट आदि बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं — सहकारिता एक भरोसेमंद और लोकतांत्रिक विकल्प हो सकती है, जो स्थायी विकास, सामाजिक न्याय और भागीदारी सुनिश्चित करे।

आगे की दिशा — सहकारिता का भविष्य

वर्तमान में सहकारिता का परिवार, ग्राम, पंचायत, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक विस्तार हो रहा है। लेकिन आगे के लिये ज़रूरी है कि —

- सहकारी संस्थाएँ पेशेवर प्रबंधन, पारदर्शिता, तकनीक-उपयोग, डिजिटल लेखा-जोखा अपनाएँ।
- युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों को नेतृत्व में शामिल करके — सहकारिता को नवाचार, उद्यमिता और समावेशन का मॉडल बनाया जाए।
- सरकार, नीतिगत संस्थाएँ, बैंक व वित्तीय संस्थाएँ सहकारिता को समर्थन दें — नीतिगत रूप से, आर्थिक रूप से और प्रशिक्षण/नेटवर्किंग के माध्यम से।
- सहकारी समितियाँ सिर्फ कृषि या बैंकिंग तक सीमित न रहकर — घरेलू उद्योग, सेवा, कारीगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार करें।

सहकारिता समाज, किसान और सरकार के लिए कैसे मददगार है?

सहकारिता की मूल भावना और सामाजिक प्रभाव

सहकारिता का आधार “साझा प्रयास – साझा लाभ” की सोच पर टिका है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक और अवसरों की दृष्टि से सशक्त बनाना है। सहकारिता संस्थाएँ समुदाय-आधारित मॉडल पर काम करती हैं, जहाँ निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और लाभ सभी सदस्यों को समान रूप से मिलता है।

सामाजिक एकता और सामूहिक निर्णय

सहकारी संस्थाएँ समाज में एकता, पारदर्शिता और सहभागिता का वातावरण बनाती हैं।

- लोग मिलकर निर्णय लेते हैं
- संसाधनों का साझा उपयोग होता है
- समुदाय में भरोसा और सहयोग बढ़ता है

रोजगार और कौशल विकास

सहकारिता ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नए रोजगार और आय स्रोत बनाने में मदद करती है। कई सहकारी संस्थाएँ प्रशिक्षण कार्यक्रम, उत्पादन इकाइयाँ और सेवा केंद्र चलाती हैं, जिससे युवाओं और महिलाओं को कौशल और अवसर मिलते हैं।

आर्थिक समावेशन

सहकारिता कम आय वर्ग के लोगों को भी आर्थिक तंत्र में शामिल करती है।

- छोटे ऋण
- बचत योजनाएँ
- सामूहिक उत्पादन
इनके माध्यम से सामान्य परिवार भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं।

किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सहकारिता की भूमिका

भारत में सहकारिता मॉडल ने कृषि और ग्रामीण विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

किसान की लागत घटाना और उपज बढ़ाना

सहकारी समितियाँ किसानों को बीज, खाद, उपकरण और संसाधन उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाती हैं। इससे:

- उत्पादन लागत कम होती है
- आधुनिक तकनीक और साधनों का उपयोग बढ़ता है
- खेती अधिक लाभकारी बनती है

फसल का उचित मूल्य और बाजार तक पहुंच

कई सहकारी संस्थाएँ किसानों की उपज को सीधे बाजार तक ले जाने में मदद करती हैं।

- बिचौलियों पर निर्भरता कम
- पारदर्शी भुगतान
- बेहतर दाम प्राप्त होते हैं

कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा

दूध, चीनी, फल-सब्जी प्रसंस्करण, बीज उद्योग जैसे कई क्षेत्र सहकारिता के माध्यम से विकसित हुए हैं। इससे कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का विस्तार होता है।

सरकार के लिए सहकारिता की उपयोगिता

सहकारिता संस्थाएँ सरकार के लिए विकास योजनाओं और समाज कल्याण कार्यक्रमों को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रभावी माध्यम बनती हैं।

विकास योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन

चूंकि सहकारी संस्थाएँ स्थानीय स्तर पर जमीनी लोगों द्वारा संचालित होती हैं, इसलिए सरकारी योजनाएँ —

- सही लाभार्थियों तक
- समय पर
- पारदर्शी तरीके से पहुंच पाती हैं।

स्थानीय स्तर पर शासन को मजबूत बनाना

सहकारिता स्थानीय नेतृत्व को सशक्त करती है, जिससे आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। यह पंचायत से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर तक शासन की दक्षता बढ़ाती है।

अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विश्वसनीयता

सहकारी बैंकों, क्रेडिट सोसाइटीज़, कृषि एवं दूध सहकारिता जैसे मॉडल अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाते हैं।

- ग्रामीण वित्तीय प्रणाली मजबूत होती है
- कृषि एवं ग्रामीण उत्पादन बढ़ता है
- स्थानीय रोजगार और आय में सुधार होता है

समाज, किसान और सरकार — तीनों के लिए लाभदायक मॉडल सहकारिता एक ऐसा ढांचा है जो तीनों स्तरों पर सकारात्मक बदलाव लाती है।

समाज के लिए

- सामूहिक स्वामित्व
- सामाजिक सुरक्षा
- सामुदायिक नेतृत्व

किसानों के लिए

- इनपुट की बेहतर उपलब्धता
- बाजार तक पहुंच
- आय में वृद्धि

सरकार के लिए

- योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन
- पारदर्शिता

- आर्थिक विकास में तीव्रता

निष्कर्ष

आत्मनिर्भर भारत में सहकारी संस्थाओं की भूमिका समय के साथ लगातार बदल रही है और नई चुनौतियों तथा अवसरों के अनुरूप विकसित हो रही है। सहकार भारती जैसी संस्थाएँ इस बदलाव की दिशा में मार्गदर्शन कर रही हैं, जहाँ पारंपरिक सहकारी मॉडल को आधुनिक तकनीक, डिजिटल प्लेटफॉर्म, नवाचार और डेटा-आधारित प्रबंधन से जोड़कर समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाया जा रहा है।

सहकारिता केवल आर्थिक लाभ का साधन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समावेशन, सामूहिक नेतृत्व, महिला और युवा सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का प्रमुख स्तंभ बन चुकी है। किसान, श्रमिक, महिला और युवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से लाभान्वित होकर न केवल अपनी आय बढ़ा रहे हैं, बल्कि समाज में सामूहिक सहयोग और समानता का संदेश भी फैला रहे हैं।

सरकार के लिए सहकारी संस्थाएँ योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और स्थिर आर्थिक विकास सुनिश्चित करने का एक भरोसेमंद माध्यम बन चुकी हैं। भविष्य में डिजिटल और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से सहकारिता का दायरा और भी व्यापक होगा, जो भारत को एक मजबूत, स्वावलंबी और समावेशी राष्ट्र बनाने में मदद करेगा।

संक्षेप में, सहकारिता आज आत्मनिर्भरता, नवाचार और सामाजिक समावेशन का एक शक्तिशाली मॉडल है, जो समाज, किसान और सरकार—तीनों के लिए समान रूप से लाभकारी है और भारत के विकास की नई दिशा तय कर रही है।

Sample Advertisement

पूर्वांचल

हड्डी अस्पताल

नरेश खन्ना
Ortho

NABH Approved

